



जगदलपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 36 बच्चों की बिगड़ी तबीयत....अस्पताल में भर्ती

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एकलव्य आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 36 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। खबरों के अनुसार, आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद कुछ बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की। बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद, स्कूल प्रशासन ने तुरंत बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती



कराया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम को मौके पर भेजा है ताकि भोजन की गुणवत्ता और अन्य संभावित कारणों की जांच की जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी और एसी ट्राइबल अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। इधर, बच्चों के परिजनों में चिंता का माहौल है।

मां ने अपने दो बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला, लार्शें जलाने की कोशिश



रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलथुगी मां ने अपने 3 साल और 5 साल के बच्चों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और शव को जलने का प्रयास किया। उसके बाद वह मौके से फरार हो गई। पड़ोसियों ने घर में उठते धुंए को देखा तो बच्चों के दादा को इसकी सूचना दी। इस दौरान पड़ोसी जब झोपड़ी के पास पहुंचे तो दोनों बच्चे भीतर लहलुहान पड़े थे। एक बच्चे का शरीर झुलसा हुआ था। पास में ही कपड़े और सामान जल रहा था। तत्काल पानी डालकर आग को बुझाया गया। इसके बाद दादा पहुंचे और उन्होंने बेटे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने महिला को तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस मामले की जांच में जुटी यह घटना रायसेन जिले के जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर देवरी गांव के वार्ड संख्या-4 में गुरुवार करीब 11 बजे की बताई जा रही है। पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता और दादा दोनों घर से करीब आधा किमी दूर एक ढाबे पर काम करते हैं। गुरुवार सुबह बच्चे दादा के साथ नजर आए थे। दादा ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दिलाई थी। इसके बाद वह काम पर चले गए थे। इस

दौरान महिला जिस झोपड़ी में रहती है, वहीं बच्चों की हत्या कर उन्हें जलाने का प्रयास किया। उसके बाद दोपहर करीब 12 बजे बच्चों की मां को बैग लेकर मेन रोड की ओर जाते देखा गया था। उस दौरान झोपड़ी से धुआं उठ रहा था। धुंए को देख बच्चों के दादा को फोन कर बुलाया गया। बच्चों की हत्या क्यों की गई, अभी इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

बार-बार बयान बदल रही महिला बताया जा रहा है कि महिला पुलिस पूछताछ में बार-बार बयान बदल रही है। पहले कह रही थी की वह पति से अलग होना चाहती थी, इसलिए बच्चों को मार डाला। फिर कहने लगी कि खुद भी मरना चाहती थी, लेकिन बच्चों की हत्या के बाद उसका मन बदल गया। वहीं महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी को 2 महीने पहले

सिर में दर्द हुआ था। उसका इलाज चल रहा था। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि महिला की किसी युवक से दोस्ती थी। वह उससे मिलने घर आया था। तब बच्चे भी घर पर थे। बच्चों ने उसे घर पर देख लिया होगा। पति से यह बात छिपाने के लिए महिला ने बच्चों की हत्या की होगी। यह बताया पुलिस ने एएसपी कमलेश कुमार ने बताया कि देवरी थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े 11 बजे राधिका आदिवासी ने बेटे और बेटी की गर्दन कुल्हाड़ी से काट दी। महिला का पति ढाबे पर काम करता है, जो घटना के समय घर पर नहीं था। पति जब घर पहुंचा, तब उसे घटना की जानकारी मिली। उसने पुलिस को सूचना दी। बच्चों के शव के पास एक जला हुआ गद्दा मिला है। गिरफ्तार आरोपी महिला से पूछताछ की जा रहे है। जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा।

पॉक्सो केस की विविटम को बार-बार कोर्ट न बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल ऑफेंस की विविटम को बयान के लिए बार-बार कोर्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट का उद्देश्य इससे प्रभावित होना। जो बच्चा सेक्सुअल ऑफेंस जैसी घटना के ट्रॉमा से गुजरता है उसे बार-बार उसी घटना के बारे में बयान के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी ने पॉक्सो एक्ट की विविटम को जिरह के लिए कोर्ट में बुलाए जाने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि एक बार आरोपी (बचाव पक्ष) को विविटम से जिरह के लिए पर्याप्त मौका दिया जा चुका है। मौजूदा मामले में विविटम के साथ काफी लंबी जिरह की जा चुकी है और यह जिरह दो बार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा-33 (5) के मुताबिक स्पेशल कोर्ट की ड्यूटी है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि चाइल्ड विविटम को कोर्ट के लिए बार-बार न बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी को चाइल्ड विविटम के साथ जिरह का कई मौका दिया जा चुका है और ऐसे में न्याय का तकाजा यही है

अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 'जूड़ो अवतार' आया सामने

नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 'जूड़ो अवतार' सामने आया है। इसमें वो मार्शल आर्ट के गुर सीखते और एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने जूडो के गुर सीखते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पहले वे मार्शल आर्ट की तकनीक को समझते नजर आ रहे हैं। यही नहीं फिर अपने विरोधी को चारों खाने चित करने भी नजर आए। राहुल गांधी ने अपने इस खास वीडियो के जरिए देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। राहुल गांधी ने इंस्टा पोस्ट में बताया कि आखिर यह वीडियो कब और कैसे बनाया गया। कांग्रेस सांसद पहले भी कई मौकों पर बता चुके हैं कि उन्हें जापानी मार्शल आर्ट आइकीडो बेहद पसंद है। वे अक्सर ही आइकीडो का नियमित अभ्यास करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कैप में भी वो सीखते नजर आए। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट सीखते और जूडो के दांव-पेच बताते वीडियो शेयर किया है। उनके वीडियो शेयर किए जाने एक महज 11 मिनट में इस वीडियो को 61 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं।

मप्र में बीएड वाले प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर आया संकट

भोपाल। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 (पहली से पांचवीं कक्षा) की नौकरी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र भेजकर उन शिक्षकों की सूची मांगी है, जिनकी नियुक्ति मानकों के अनुरूप नहीं है। डीपीआई ने निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाए। बता दें कि जिन शिक्षकों ने बीएड किया है और जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उन सभी शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। डीपीआई के संचालक ने अगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्यापुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़,



उज्जैन, विदिशा सहित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। हालांकि, 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक अपनी नौकरी बनाए रखेंगे। यह फैसला केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के जून 2018 के आदेश के पालन में लिया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया था, जिसमें डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) धारकों का तर्क था कि बीएड

धारक उनके हक की नौकरी ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के आदेश को शून्य कर दिया। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने भी 3 मई 2024 को मध्यप्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। अब डीपीआई ने यह आदेश जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही जिलों को कार्रवाई के लिए कहा गया है।

सदस्य बनाने के लिए मदरसों और दरगाहों पर पहुंचेगी बीजेपी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान की तैयारियां कर ली हैं। खबर है कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी पार्टी में 50 लाख सदस्य शामिल करने का लक्ष्य रखा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए पार्टी मदरसा और दरगाह समेत कई स्थानों तक पहुंचेगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों को भी भाजपा शामिल कराने की कोशिश अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की मौजूदगी में वर्कशॉप का आयोजन हुआ था। इसमें अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू भी शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सिद्दीकी ने बताया था कि सदस्यता



अभियान 2 सितंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। 1 सितंबर से शुरू हो रही प्राथमिक सदस्यता अभियान का आयोजन मोर्चा 2 चरणों में करेगा। उन्होंने बताया कि पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। अल्पसंख्यक मोर्चा का लक्ष्य देश में 50 लाख सदस्य जोड़ने का है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी समुदाय तक पहुंचेगा, जिसके लिए 14 हजार सूफी वार्ता टीमों काम करेंगी।

हाईकोर्ट का बीजेपी नेता से सवाल

किस आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे बृजभूषण

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से गुरुवार को पूछा कि वे किस आधार पर अपने खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामले में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट अभियोजन के साक्ष्य दर्ज कर रही है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सिंह की ओर से पेश एडवोकेट राजीव मोहन को इस बाबत शॉर्ट नोट बनाकर कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। शिकायतकर्ताओं



का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने किया। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बृजभूषण ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024: इतिहास में पहली बार भारत में 1500 से अधिक लोगों के पास 1,000 करोड़ की संपत्ति

मप्र में आठ टॉप अमीर कारोबारी, विनोद अग्रवाल एमपी के सबसे अमीर शरत्स

नई दिल्ली। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 गुरुवार को जारी हुई। इसमें भारत के 334 अरबपतियों के नाम हैं। यह 13 साल पहले जारी हुई लिस्ट से 6 गुना ज्यादा है। लिस्ट के मुताबिक देश के सबसे अमीर लोगों में अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और शिव नादर हैं। हुरुन रिच लिस्ट 2024 में 1,500 से अधिक व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1,000 करोड़ या उससे अधिक है। यह सात साल पहले की तुलना में 150ब की बढ़ोतरी को दिखाता है। हुरुन इंडिया ने कुल 1,539 अति-धनवान व्यक्तियों की पहचान की है, जो पिछले साल की तुलना में 220 की उल्लेखनीय बढ़ोतरी को दिखाता है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में मध्यप्रदेश के कई कारोबारियों के भी नाम हैं। इंदौर के कोल कारोबारी विनोद अग्रवाल मध्यप्रदेश के सबसे अमीर शरत्स हैं। हुरुन रिच लिस्ट में उन्हें 394वीं रैंक मिली है। मध्यप्रदेश कैटेगरी में वे नंबर एक पर बरकरार हैं। 2023 में उनकी संपत्ति 6700 करोड़ थी। एक साल में 400 करोड़ का इजाफा हुआ। अब वे बढ़कर 7100 करोड़ हो गई है। लिस्ट में मध्यप्रदेश कैटेगरी में उजास एनर्जी के श्याम सुंदर गेंदालाल मूंदड़ा 3500 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरी और 3400 करोड़ संपत्ति के साथ शक्ति पंप के दिनेश पाटीदार तीसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में पाटीदार परिवार के सुनील पाटीदार 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 8वें नंबर पर हैं।

मध्यप्रदेश कैटेगरी में ये हैं टॉप कारोबारी

- अग्रवाल कोल के विनोद अग्रवाल की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 394वीं रैंक। इनकी संपत्ति 7100 करोड़ रुपए है।
- उजास एनर्जी के श्यामसुंधर गेंदालाल मूंदड़ा की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 709 वीं रैंक। इनकी संपत्ति 3500 करोड़ रुपए।
- राजरतन ग्लोबल वायर के सुनील चौरडिया की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 1016वीं रैंक। इनकी संपत्ति 2100 करोड़ रुपए।
- जीआर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स के विनोद कुमार अग्रवाल की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 1192वीं रैंक। इनकी संपत्ति 1700 करोड़ रुपए।
- जयदीप इस्पात एंड एलाय के विनोद तोड़ी की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 1298वीं रैंक। इनकी संपत्ति 1500 करोड़ रुपए।
- प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एंड टोल हाईवे के नितिन अग्रवाल की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 1378वीं रैंक। इनकी संपत्ति 1300 करोड़ रुपए।

मध्यप्रदेश कैटेगरी में ये कारोबारी हुए बाहर

मध्यप्रदेश कैटेगरी में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शामिल कुछ कारोबारी 2024 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यानी इनकी संपत्ति 1000 करोड़ से नीचे पहुंच गई है। ऐसे ही कारोबारी हैं सुधीर अग्रवाल जिनकी संपत्ति 2023 की लिस्ट में 2700 करोड़ रुपए थी। वहीं दिलीप सूर्यवंशी भी 2024 की लिस्ट से बाहर हैं। इनकी संपत्ति 2023 में 2600 करोड़ रुपए थी। इसी तरह साल 2023 की सूची से तुलना करें तो इस सूची में से सुधीर अग्रवाल बाहर हो गए हैं जिनकी संपत्ति 2700 करोड़ रुपए थी। इसी तरह दिलीप सूर्यवंशी की संपत्ति बीते साल 2600 करोड़ रुपए थी वे भी इस सूची से बाहर हैं। 2023 की लिस्ट में 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले देवेंद्र जैन का नाम भी 2024 की लिस्ट में नहीं है। मनीष डबकरा का नाम भी 2024 की लिस्ट में नहीं है। वे 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ 2023की लिस्ट में शामिल थे।



ओला के इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग, 2,500 लोगों को बचाया

इंदौर। इंदौर की बहुमंजिला इमारत में स्थित बिजली से चलने वाले वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम में गुरुवार शाम आग लग गई। घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना के दौरान इमारत में मौजूद करीब 2,500 लोगों को सुरक्षित बचाया, जिनमें लगभग 10 कोचिंग सेंटर के करीब 2,000 विद्यार्थी शामिल हैं। सहायक पुलिस आयुक्त (एसोपी) तुषार सिंह ने बताया कि गोता भवन चौराहे के पास छह मंजिला वाणिज्यिक इमारत में ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम में आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद एहतियात के तौर

पर यह इमारत खाली करा ली गई और करीब 2,500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, इनमें ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम के छह कर्मचारी और करीब 10 कोचिंग सेंटर के लगभग 2,000 विद्यार्थी शामिल हैं।

आग पर काबू पाने के लिए करना पड़ी कड़ी मशक्कत- एसोपी के मुताबिक इस इमारत में ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम के बिल्कुल पास एक कार कंपनी के शो-रूम के अलावा दफ्तर और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी हैं, लेकिन आग पर समय रहते काबू पाए जाने के चलते इसकी लपटें अन्य स्थानों तक नहीं पहुंच सकीं। सिंह ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि

हमें आशंका है कि शो-रूम में शॉर्ट सर्किट होने या बैटरी फटने से आग लगी होगी। हालांकि, जांच के बाद ही इसका सटीक कारण बताया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम में रखी 10-12 गाड़ियों को नुकसान होने के बारे में पता चला है।

दूर तक दिखाई दे रहा था धुआं- आग इतनी विकराल थी कि दूर तक धुआं देखा जा सकता था। फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम आग पर काबू पाया। यहां दो गाड़ी से चार टैंकर से हजारों लीटर पानी डाला गया। आग से किसी तरह की जन हानि नहीं हुई। ओला शोरूम में आग की घटना से लाखों रुपये माल जलकर खाक

हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर बड़ी संख्या पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद रहे।

बैटरी से चिंगारी निकलने से लगी आग- एसोपी ने बताया कि घटना से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है और जांच जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के दौरान ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम से गहरा काला धुआं निकलता दिखाई दिया। अग्निशमन दस्ते के सहायक पुलिस निरीक्षक (एएसआई) सुशील कुमार दुबे ने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक के शो-रूम के कर्मचारियों के मुताबिक वे कुछ काम रहे थे और इस दौरान बैटरी से चिंगारी निकलने के कारण आग लग गई।



पुलिस से दूर भागने वाले लोग भी आना चाहते हैं ‘शुभी’ के सामने

इंदौर। देश में लोगों को ट्रैफिक नियम समझाते-समझाते पुलिस वाले थक जाते हैं। लोगों को यह समझ नहीं आता कि जितने भी यातायात नियम हैं, वो उनकी ही सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। हेलमेट पहनने से लेकर सीट बेल्ट लगाने तक के नियमों का सीधा रिश्ता लोगों की सुरक्षा से है, लेकिन लोग अगर ट्रैफिक नियम मानते हैं तो सिर्फ चालान कटने के डर से। कई लोगों को तो जहां ट्रैफिक पुलिस नजर आ जाते हैं, वो अपना रास्ता ही बदल देते हैं। जहां लोग ट्रैफिक पुलिस से दूर ही रहना चाहते हैं, वहीं इंदौर की सड़कों पर एक ऐसी महिलाकर्मौ तैनात होती है, जिसे देखने के लिए कई लोग तो जानते हुए उस एरिया से क्रॉस करते हैं। सादगी की मिसाल और अपने काम से प्यार की वजह से यह महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मौ लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर इनके कई वीडियोज शेयर किये गए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं।



इशारों में कुछ यूं समझाती हैं बातें

हम बात कर रहे हैं इंदौर की यातायात प्रबंधन मित्र शुभी जैन की। शुभी को सड़कों पर ट्रैफिक संभालते देखा जा सकता है। अपने टैलेट और काबिलियत की वजह से उन्हें वॉलन्टियर कैपेन का ब्रांड एम्बेस्डर भी बनाया जा चुका है। शुभी कभी रैडियो जॉकी हुआ करती थी, लेकिन अब वो सड़कों पर लोगों को यातायात नियमों बताती हैं। उनके अंदाज को देखने के लिए कई लोग सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और उनके वीडियोज बनाने लगते हैं।

सोशल मीडिया पर है वायरल

खुद शुभी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनके कई फॉलोवर्स हैं। इसके अलावा वे अपने काम के वीडियोज बनाकर उसे भी पोस्ट करती हैं। शुभी के मुताबिक, यह काम उन्हें सुकून देता है। अगर उनके समझाने की वजह से एक भी शख्स ट्रैफिक नियम का पालन करने लगता है तो उनके लिए ये काफी खुशी की बात है। हल ही में शुभी ने अपने वर्क प्लेस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लाखों बार देखा गया। शुभी के इस तरह के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।

धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने पर दो अफसरों को अवमानना नोटिस

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी संभागायुक्त इंदौर तथा कलेक्टर खंडवा ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति संबंधित आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा पर नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन नहीं करने पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बसंत ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए हैं। खंडवा निवासी लव जोशी तथा शेख जावेद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाए जाने के आदेश जारी किए थे। खंडवा में जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में जनवरी 2024 में सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी। बैठक में कहा गया था, कोलाहल एक्ट की धारा-7 के



तहत धार्मिक स्थलों में निर्धारित ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश करें। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक्ट में दिए गए प्रावधान के तहत जिला कलेक्टर खंडवा तथा संभागायुक्त इंदौर के समक्ष आवेदन पेश किया। आवेदन पर उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 मई को आदेश जारी किया था कि

30 दिनों की निर्धारित समय अवधि में आवेदन का निराकरण किया जाए। निर्धारित समय अवधि के बाद भी दोनों अधिकारियों ने आवेदन का निराकरण नहीं किया, जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 14 सितम्बर को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पेरवी की।

इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पुणे में छटे माले से कूद कर दी जान

इंदौर। इंदौर निवासी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती ने पुणे में छटे माले की एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी। चार माह पहले ही युवती की शादी पुणे निवासी केसरीनंदन कर्ण से हुई थी। शादी के बाद से ही युवती को ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। जान देने से पहले युवती ने अपने पिता को मैसेज भी किया था। इसमें उसने तीन दिन से कमरे में बंद रखने, खाना नहीं देने जैसी बातों का जिक्र किया था। इंदौर निवासी खुशबू जर्मींदार पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। उसने कंपनी में ही काम करने वाले केसरीनंदन से शादी की थी। वह मूलतः बिहार का है। पुणे में वह अपने माता-पिता के साथ कोहिनूर सफायर में रहता है। शादी के बाद से ही खुशबू को उसके माता-पिता ने टोकना शुरू कर दिया था और बात-बात पर ताने मारते थे। यह बात वह सहस नहीं कर पाती है।



खुशबू का भाई भी पुणे के अस्पताल में जाँब करते हैं। वह डॉक्टर है। खुशबू ने अपने भाई को भी ससुराल वालों द्वारा तंग किए जाने की बात बताई थी। खुशबू ने आत्महत्या से पहले अपने पापा को मैसेज किया था, लेकिन वे देख नहीं पाए। मैसेज में खुशबू ने कहा था कि उसके साथ सास ससुर और पति ने मारपीट की। तीन दिन तक कमरे में बंद रखा। खाना भी नहीं

दिया। जब मैंने एक सेवफल खाने की कोशिश की तो वह भी छिन लिया। अब मैं और जीना नहीं चाहती। बुधवार शाम को मौका पाकर वह फ्लैट से निकली और छटे माले से कूद कर जान दे दी। परिजनों ने सास-ससुर और पति की शिकायत पुलिस को की है। युवती के हाथ और पैर पर शारीरिक प्रताड़ना के निशान भी मिले हैं।

इस तरह काम करती हैं शुभी जैन

कोविड-19 से पहले इंदौर में यातायात प्रबंधन करते समय अपने अनोखे डांस मूव्स के लिए चर्चा में आई शुभी जैन को इंदौर ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक वॉलंटियरिंग पहल के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। यातायात प्रबंधन मित्र के नाम से जानी जाने वाली इस पहल में छात्रों और पेशेवरों सहित लगभग 250 स्वयंसेवक शामिल हैं, जो शहर भर में विभिन्न बिंदुओं पर यातायात को विनियमित करने में इंदौर ट्रैफिक पुलिस की सहायता करते हैं। शुभी जैन कहती हैं कि वॉलंटियरिंग के दौरान उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। कोई भी नहीं चाहता कि कोई आकर उन पर चिल्लाए या हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने के लिए उन्हें दंडित करे। आप क्रोधित और निराश हो जाते हैं, खासकर अगर आप एक लंबे और तनावपूर्ण दिन के बाद घर लौट रहे हों। शुभी ने नियमों का पालन करने वालों को सलाम करना और उनका धन्यवाद करना शुरू कर दिया। कानून तोड़ने वालों को संबोधित करते समय, वे उनसे विनम्रता से पेश आती हैं, उनसे नियमों का पालन करने का आग्रह करती हैं, और वे देखती हैं कि ज्यादातर लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। शुभी गर्व से कहती हैं, प्रशंसा पाने वालों को देखकर, उत्कंघनकर्ता भी नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं।

ढाई साल की बच्ची दूसरी मंजिल से गिरी, हो गई मौत



परिवार के बाकी सदस्य काम पर गए हुए थे। परिवार के मुताबिक बादल की शादी को चार साल के लगभग हो गए। उनका परिवार खेती किसानी करते हैं। परिवार ने बताया कि साक्षी उनकी इकलौती बेटी हैं। मां को बेटी मौत को लेकर सुबह तक जानकारी नहीं दी गई थी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है।

जोनल अधिकारी को मंत्री-मेयर के नाम से धमकाया, केस दर्ज



इंदौर। इंदौर नगर निगम के जोनल अधिकारी के केबिन में घुसकर साथ बंदसलूकी करने और धमकाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल निगम की टीम ने वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल मामले में चालानी कार्रवाई की थी, उस पर से विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों ने जोनल अधिकारियों को मंत्री और मेयर के नाम से धमकाया। इसके बाद जोन अध्यक्ष ने जोनल अधिकारी को थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले का वीडियो भी सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर को प्रगति नगर, राजेंद्र नगर में हुई थी। जोन-21 के जोनल अधिकारी राहुल रघुवंशी वार्ड 80 के 297 राज लक्ष्मी पैराडाइज पहुंचे थे। वहां उन्होंने वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल देखा तो टीम को मोके पर मलबा हटाने और चालान बनाने के लिए भेजा। टीम वहां पहुंची और चालान बनाया। कुछ देर बाद इस बिल्डिंग से जुड़े गोविंद गुप्ता और आनंद गुप्ता जोनल ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने जोनल अधिकारी राहुल रघुवंशी से बंदसलूकी की और धमकियां दी। उन्होंने कहा कि परिवार का मामला है। अभी मेयर को कोन लगाता हूं। साथ ही धमकी दी कि मंत्री के परिवार का मामला है, चालान कैसे बना दिया। इस दौरान निगम कर्मियों ने घटना का वीडियो बना लिया। इस बीच जोन अध्यक्ष प्रशांत बडवे को सूचना मिली तो वे भी मोके पर पहुंचे तो संबंधित पक्ष द्वारा दबाव-प्रभाव बनाने की कोशिश की। चुकि मामला गंभीर था इसलिए बडवे जोनल अधिकारी के साथ राजेंद्र नगर थाने पहुंचे। इधर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा तक भी वीडियो पहुंचा तो उन्होंने भी सख्त कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद जोनल अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने गोविंद गुप्ता और आनंद गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है।

इंदौर में छोटे उद्योगों की संख्या 5 हजार पार निर्माण क्षेत्र को राज्य से मदद की दरकार

इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) की संख्या पांच हजार के पार पहुंच गई है। ये वे उद्योग हैं जो उत्पादन और निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मगर, उसमें निर्माण क्षेत्र की वृद्धि नजर नहीं आती। लघु उद्योग और औद्योगिक संयंठन लगातार छोटे उद्योगों को सरकार की नीतियों में संरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। उद्योगों के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और व्यापार घाटा कम करने के लिए छोटे उद्योग संजीवनी साबित हो सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मप्र के आंकड़ों



के अनुसार, इंदौर क्षेत्र में करीब पांच हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं। ये किसी तरह का उत्पादन, निर्माण या प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसके मुकाबले कम से कम दो गुना इसी श्रेणी रजिस्टर्ड उद्योग भी हैं।

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अनुसार, मप्र की अर्थव्यवस्था 11 से 12 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है। यदि व्यापार घाटा कम कर लिया, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार इससे कहीं अधिक हो जाएगी।

मैन्युफैक्चरिंग उद्योग वह मंत्र है, जो सीधे तौर पर व्यापार घाटे को कम कर सकता है। निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो प्रदेश के उत्पाद से जरूरतें तो पूरी होंगी। यहां से ज्यादा निर्यात भी होगा। ऐसे में सरकार का आयात बिल घटेगा और व्यापार घाटा भी कम होगा। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर में सीधा उछाल दर्ज होगा। साथ ही उसे बैंक के ब्याज के मुकाबले तीन गुना ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इस नियम को लागू हुए एक वर्ष से ज्यादा समय हुआ है। इसका असर है कि छोटे उद्योगों के भुगतान में तेजी आई है। लिहाजा राज्य भी खरीद व अन्य नीति बनाकर छोटे उद्योगों को राहत दे सकती है। -सीए स्वप्निल जैन, पूर्व सचिव प्राथमिकता का नियम जल्द

हो लागू महाराष्ट्र हो या अन्य पड़ोसी राज्य, वहां की सरकार ने नियम लागू कर रखा है कि प्रदेश की आपूर्ति में स्थानीय छोटे उद्योगों को प्राथमिकता और वरीयता दी जाएगी। सरकार और विभाग उपकरण से लेकर दवाएं घटेगा और व्यापार घाटा भी कम होगा। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर में सीधा उछाल दर्ज होगा। साथ ही उसे बैंक के ब्याज के मुकाबले तीन गुना ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इस नियम को लागू हुए एक वर्ष से ज्यादा समय हुआ है। इसका असर है कि छोटे उद्योगों के भुगतान में तेजी आई है। लिहाजा राज्य भी खरीद व अन्य नीति बनाकर छोटे उद्योगों को राहत दे सकती है। -सीए स्वप्निल जैन, पूर्व सचिव प्राथमिकता का नियम जल्द

संपादकीय

ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे कठिन समय

‘दीदी’ के संभ्रांत शहर कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में इयूटी कर रही टे:नी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई और बाद में हत्या कर दी गई, उससे समूचा देश शर्मसार है। साझा आंदोलन का मुद्दा यही है। यह ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे कठिन समय है, क्योंकि छात्रों, युवाओं और महिलाओं के समवेत आंदोलनों ने ही ममता को सडक से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया था। आज ममता ऐसे ही आंदोलनों के युवाओं और छात्रों को ‘गुंडा’ करार दे रही हैं।

यह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अग्नि-परीक्षा का दौर है। बंगाली सम्मान से उन्हें ‘दीदी’ कहते रहे हैं, लिहाजा जवाब भी उन्हीं से मांग रहे हैं। ‘दीदी’ के खिलाफ आंदोलन-दर-आंदोलन जारी हैं। यह स्थिति तब है, जब दो माह पहले लोकसभा चुनाव में उनकी तृणमूल पार्टी को 46 फीसदी वोट मिले और 42 में से 29 सीटें जीतीं। इस जनादेश की आड़ में आप नहीं छिप सकतीं, क्योंकि राज्य की युवा और छात्र शक्ति गुस्से और आक्रोश में है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा का विरोध-प्रदर्शन और 12 घंटे का बंद भी आयोजित किया गया और 3 सितंबर को वाममोर्चा का कांडर सडकों पर उतरेगा। सभी की साझा मांग है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं हुआ है। ‘दीदी’ के संभ्रांत शहर कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में इयूटी कर रही टे:नी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता की गई और बाद में हत्या कर दी गई, उससे समूचा देश शर्मसार है। साझा आंदोलन का मुद्दा यही है। यह ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे कठिन समय है, क्योंकि छात्रों, युवाओं और महिलाओं के समवेत आंदोलनों ने ही ममता को सडक से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया था। आज ममता ऐसे ही आंदोलनों के युवाओं और छात्रों को ‘गुंडा’ करार दे रही हैं। बंगाल पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां भांजी, पानी की तेज धार मारी, आंसू गैस के गोले दागे और बाद में हिरासत में भी बंद कर दिया। सचिवालय तक के रास्ते में 27 बैरिकेड्स स्थापित किए, 26 डीसीपी सरीखे वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए, 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान तैनात किए। लोहे की दीवारें खड़ी की गईं, जिन पर तेल और ग्रीस मला गया। क्या कोई रणक्षेत्र सजा था? ‘दीदी’ ने किससे युद्ध करने को अपने जवान तैनात कराए थे? आंदोलनकारी ‘नबन्ना सचिवालय’ तक मार्च करना चाहते थे और डॉक्टर बटिया के साथ ‘रेप-मर्डर’ की नृशंसता का न्याय मांग रहे थे। आंदोलन और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन तो हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आंदोलनकारियों ने कुछ पथराव किया, तो उनके मानसिक रोष को समझना चाहिए था। आंदोलन की ताकत इसी से समझी जा सकती है कि 80,000 से अधिक युवा और छात्र सडक पर आंदोलित हुए। यह ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ सामूहिक लहर का एक प्रमाण है। यह 2026 के जनादेश को भी तय कर सकता है। ममता-विरोधी आंदोलनों ने कोलकाता के बाहर और पश्चिम बंगाल के पार खासकर बंगालियों को जगा दिया है। यह उनके लिए चेतावनी की घंटी है। औसतन बंगाल महिला-सुरक्षा और सम्मान का पक्षधर रहा है। बंगाल देवी दुर्गा और मां काली की आराधना-स्थली है। अगले माह दुर्गा पूजा और फिर दीपावली के त्योहार हैं। आह्वान किए जा रहे हैं कि ये त्योहार न मनाए जाएं। आखिर एक बेटी को कुचल कर मारा गया है। ईसाफ अभी निश्चित नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है। साक्ष्य मिटा दिए गए थे, जब हजारों की भीड़ एक रात में अचानक अस्पताल तक आई और सब कुछ तबाह कर दिया। बंगाल पुलिस उस भीड़ को तो रोक नहीं पाई। बल्कि उसकी खुफिया सूचना तक हासिल नहीं कर पाई। ‘दीदी’ को इन सभी अपराधों के जवाब देने होंगे। कोलकाता के आंदोलनकारी ‘दीदी’ ममता की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। ‘रेप-मर्डर’ बर्बर मामले के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने ही अस्पताल के प्रशासन और पुलिस के निकम्मेपन का बचाव किया है, लिहाजा ममता की भूमिका को भी अक्षम्य माना गया। सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ ने ऐसी ही तल्ल टिप्पणियां की थीं। ममता इन आंदोलनों को राम-वाम और कांग्रेस पर थोप कर अग्नि-परीक्षा पार नहीं कर सकतीं। राज्य के गवर्नर लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। अभी वह दिल्ली में राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात करके लौटे हैं, लिहाजा बंगाल में अनुच्छेद 356 के तहत ‘राष्ट्रपति शासन’ लगाने की चर्चाएं भी जारी हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम है, संवैधानिक मशीनरी ढह चुकी है, कानून-व्यवस्था अराजक स्थिति में है, अपराध बढ़ रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं भी की जा रही हैं, लिहाजा 356 का यह फिट केस है, लेकिन ममता ‘सड़किया राजनेता’ हैं। वे फिर सडक पर बिछ सकती हैं। सहानुभूति ग्रहण कर सकती हैं, लिहाजा 356 चरप्पा करना है, तो गंभीर विमर्श के बाद किया जाना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आंदोलित युवाओं पर पुलिसिया बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है। क्या रेप व हत्या की शिकार हुई प्रशिक्षु चिकित्सक को न्याय नहीं मिलना चाहिए। लगता है जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा।

बंगाल की सियासत में हिंसा हर दिन की बात

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला जुनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में राज्य सचिवालय नबन्ना तक मार्च के दौरान इस सप्ताह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भारी झड़पें हुईं। इससे पहले, इस जघन्य अपराध के विवरण सामने आने और पुलिस की निष्क्रियता के बाद, पूरे बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग सडकों पर उतर आए। मांग ‘रीकेव्ड द नाइट’ की यानी रात में भी बेधड़क और सुरक्षित घूमने की आजादी। लेकिन प्रदर्शनों में कुछ संगठित हिंसा का सामना करना पड़ा और जिस अस्पताल में अपराध हुआ था, वहां लक्षित बर्बरता की घटनाओं ने विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करने की संभावना को नष्ट करने का प्रयास किया। हम अभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते हैं कि युवती को आखिर क्या पता चल गया था जिसके कारण उसे क्रूर तरीके से चुप करा दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य मशीनरी की विफलता की निंदा की। लेकिन भीड़ खुद राज्य मशीनरी का एक हिस्सा है। ध्यान दें कि

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने कथित कार्यकर्ताओं की हिंसा से खुद को दूर रखा है, और प्रदर्शनकारियों की मांगों के साथ खड़े होने की कोशिश की। स्थानीय हिंसा पर नियंत्रण बंगाल की राजनीति की मुख्य विशेषता है, जो कम से कम 1946 के कुछथात कलकत्ता हत्याकांड के बाद से स्पष्ट है, जब मुस्लिम लोग के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा हिंसा का आह्वान गुंडा-संचालित गिरोहों द्वारा हजारों लोगों की हत्या में बदल गया था। गुंडे राज्य में पार्टी की राजनीति की धुरी बन हुए हैं। यह वाम मोर्चे के लिए उतना ही सच है जितना कि तृणमूल के लिए। इससे पहले, बंगाल कांग्रेस ने तत्कालीन सीएम सिद्धार्थ शंकर रे के तहत धमकाने की प्रथाओं का खुलकर इस्तेमाल किया, जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अनौपचारिक और राज्य प्रायोजित हिंसा का शासन चलाया। अब तक, बंगाल गुंडों के लिए एक प्राकृतिक आवास बन चुका है। गुंडा यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास राजनीतिक संपर्क हैं और जो अनौपचारिक हिंसक बल में श्रमिकों को संगठित करने में सक्षम है।

क्या सध पा रहा है पहले की तरह शक्ति का संतुलन?

पिछले एक वर्ष से अशांत मणिपुर समस्या का मूल कारण आरक्षण से संबंधित रहा है। यहां के मूल निवासी मैतेई बहुसंख्यक होने के बावजूद आरक्षण दायरे से बाहर होने के नाते कई प्रकार की समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। यह समुदाय अपने ही प्रांत में कहीं भी भूमि क्रय कर बस नहीं सकता है। वहीं यहां लागू दोहरे आरक्षण विधानों के नाते भूमिपुत्र मैतेई सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त हिस्सेदारी से वंचित है। ऐसे में इनके पक्ष में आए न्यायिक निर्णय के बावजूद भाजपा सरकार इन्हें आरक्षण दायरे में शामिल करने मे अक्षम सिद्ध हुई है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। इस बयान में उन्होंने कहा है की हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के निहितार्थ को समझाने के लिए मोदी सरकार के हालिया निर्णय ही पर्याप्त है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के मौजूदा स्वरूप पर एक निर्णय आया है। इसमें आरक्षण लाभार्थियों में से सुसम्पन्न परिवारों को बाहर किए जाने की सिफारिश की गई है। दरअसल, कुछेक परिवार ही पीढ़ियों से इसका लाभ लेते आए हैं। इधर एक बड़ा तबका अब भी विकास से कोसों दूर है। ऐसे में इन अभावग्रस्त परिवारों के उन्नयन हेतु यह आवश्यक है कि इस वर्ग से आने वाले सुसम्पन्न परिवार सुविधाओं का परित्याग करें। इनके द्वारा छोड़ी गई सुविधाओं के लाभार्थी केवल इनकी ही जाति एवं सामाजिक वर्ग के हित में होना है। ऐसा नहीं है कि माननीय न्यायालय ने बिना प्रमाणों एवं विचार के ही अपना मतव्य रखा है। इसके अपने कारण है दरसल हर शासकीय जनगणना एवं विभिन्न सर्वेक्षणों के उपरांत इस विषमता के साक्ष्य प्रमाण मिलते रहे है। इस नाते कई दलित बुद्धिजीवी एवं नेताओं ने भी आगे आकर बदलाव की बात की है। इधर, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस बदलाव का स्वागत किया है। वहीं राजस्थान के पूर्व मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस बदलाव को जरूरी बताया है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय पासवान उन गिने-चुने दलित बुद्धिजीवी एवं राजनेता के तौर पर है जो इस बदलाव के हमेशा से हिमायती रहे है। यही नही उन्होंने अपने बचचों को भी आरक्षण का लाभार्थी बनने नहीं दिया है। इस बीच इससे मिलते जुलते एक और मामले पर भी मोदी सरकार अपने निर्णय से पलटी मार चुकी है। अभी हाल ही में भारत सरकार के कुछेक प्रशासकीय पदों पर सीधे नियुक्ति का मामला था, जिनके अंतर्गत विभाग विशेष मे कार्य विशेषज्ञताओं से परिपूर्ण अनुभवी एवं बेहद पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्ति



होनी थी। सरकार के चौबीस मंत्रालयों मे ऐसे करीब पैंतालीस अधिकारियों की नियुक्ति अगले पांच वर्ष के लिए होनी है। ऐसी नियुक्तियों का दुनियाभर में चलन है अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक मे यह प्रभावी है। किंतु इस पर भी राहुल गांधी द्वारा सवाल खड़ा किया गया है। यहां बजाय इनके उपयोगिता एवं योग्यता पर प्रश्न की जगह नियुक्ति मे आरक्षण न होने को तूल दिया गया है। जबकि एकल पदों पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। वहीं अतीत के कांग्रेस सरकार में ऐसी नियुक्तियों के कई उदाहरण है। जिसके अंतर्गत मनमोहन सिंह,मॉन्टेक सिंह अहुवालिया,रघुराज रामन सैम पित्रोदा एवं सोनिया गांधी लाभांन्वित हुई है। किंतु विपक्ष द्वारा बनाए गए मुद्दे को लेकर सरकार यहां भी अपने निर्णय से पीछे हटी है। जिसकी परिणति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस विज्ञापन के जारी होने के तीसरे दिन इसका निरस्त होना है। वैसे इन मुद्दों का सबसे असमंजसपूर्ण पहलु सरकार मे बैठे लोगों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों का आना है। बात प्रशासकीय सेवा चयन मुद्दे की करे तो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के वक्तव्य बेहद सधे थे। आरक्षित वर्ग आने वाले इस पूर्व नौकरशाह ने इसके विषय मे बेहतरीन दलीलें दी थी। किंतु इसी मुद्दे पर मंत्री चिराग पासवान ने विरोध पूर्ण वक्तव्य देने का काम किया। वहीं सहयोगी दल जदयू ने भी असहमति प्रकट की है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। वैसे केवल ऐसे दो मामले ही नहीं हैं। इसी महीने केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु एक संशोधन विधेयक लाया था, जिसे विपक्ष के विरोधी तेवर को देखते हुए अकारण संयुक्त संसदीय समिति के हवाले कर दिया गया, जिसके प्रतिनिधि सत्ता एवं विपक्ष दोनों के सदस्यगण होते हैं। ऐसे में अब इस बात की पूरी आशंका है कि यह प्रारूप अधर में लटकेगा। अगर यह

सदन पटल पर आया तो भी अपने मूल सुधारात्मक स्वरूप में कतई नहीं होगा। दरअसल लगातार ऐसे संशयात्मा निर्णय सरकार की मंशा,प्रगतिशील सोच एवं बदलाव संबंधित प्रयासों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। वहीं यह निश्चित ही विपक्षी दबाव और सत्ता पक्ष के आपसी समन्वय के अभाव का सूचक है। अन्यथा चिराग पासवान तथा नीतीश कुमार की पार्टी सार्वजनिक रूप से भला क्यों विभिन्न मुद्दों पर असहमति प्रकट करती? वहीं वक्फ विधेयक पर तेलगुदेशम द्वारा न्यायिक संवैधानिक पहलुओं के विचार की जगह मजहबी मौलानाओं से संवाद का सुझाव भी निश्चित ही इसी प्रकार का है। ऐसे ही सोच और समझ का परिणाम अब समान नागरिक संहिता की जगह पंथ निरपेक्ष नागरिक कानून की बात है। प्रधानमंत्री ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से इसके लिए जाने की बात की है। जबकि यह नागरिकों के बीच बिना किसी भेदभाव के एक समान अधिकार व्यवहार एवं दंडविधान की वकालत करता है। यह संविधान की मूल भावनाओं की न्याय सम्मत अभिव्यक्ति है। किंतु जब देश के प्रधानमंत्री ही इसे लेकर ऐसे संशय तथा परिवर्तनों वाले सोच से भरे हों, ऐसे में इसका भी हथ्र निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दरसल अतीत के कई ऐसे मसलें हैं जिस पर प्रभावी पहल के बावजूद भाजपा सरकार असफल सिद्ध हुई है। यहां तक कि कई मामलों में तो न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी भाजपा शासन इन निर्णयों पर अडिग नहीं रही। पिछले एक वर्ष से अशांत मणिपुर समस्या का मूल कारण आरक्षण से संबंधित रहा है। यहां के मूल निवासी मैतेई बहुसंख्यक होने के बावजूद आरक्षण दायरे से बाहर होने के नाते कई प्रकार की समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। यह समुदाय अपने ही प्रांत में कहीं भी भूमि क्रय कर बस नहीं सकता है। वही यहां लागू दोहरे आरक्षण विधानों के नाते भूमिपुत्र

मैतेई सरकारी नौकरियों मे भी पर्याप्त हिस्सेदारी से वंचित है। ऐसे में इनके पक्ष में आए न्यायिक निर्णय के बावजूद भाजपा सरकार इन्हें आरक्षण दायरे में शामिल करने मे अक्षम सिद्ध हुई है। विदेशी शक्तियों के षड्यंत्र एवं विपक्षी राजनैतिक दबाव के नाते ऐसे कई घटनाक्रम विगत वर्षों में हुए है। 2021 में तेरह महीनों तक चला किसान आंदोलन भी कुछ ऐसा ही था। आंदोलन की आड़ में अलगाववादी शक्तियां अराजकता को बढ़ावा दे रही थीं। वहीं यह देश की छवि को खराब करने तथा सरकार को अस्थिर करने का भी उपक्रम था। बात अगर सुधारों की हो तो पूर्ववर्ती सरकारों के समय आए कृषि सुधार प्रस्तावों को तीन कृषि कानूनों के द्वारा इस सरकार में लाया गया था। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ.स्वामीनाथन की पूरी रिपोर्ट जो की कांग्रेसनीत गठबंधन सरकार के दौरान आई थी वो पूरी की पूरी लागू होनी थी। किंतु मोदी सरकार अपने इस निर्णय पर भी कायम नही रह पाई। वैसे यह मोदी शासन के पूर्ववर्ती कार्यकाल की इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलित उत्पीड़न अधिनियम के दुरुपयोग पर रोक लगाने का निर्णय दिया है, जिसके उपरांत विरोध प्रदर्शनों को देखकर भाजपा शासन ने इसे संसदीय प्रस्ताव से पलट दिया था। विदित हो कि ऐसा ही एक न्यायिक निर्णय शाहबानों प्रकरण भी हुआ था। जबकि इन सभी निर्णयों का सीधा संबंध देश की तीव्र गति विकास एवं शांतिपूर्ण सामाजिक ताने-बाने से रहा है। इस बीच सबसे दुखदाई बात है सरकार,भाजपा पार्टी और इससे जुड़े आरएसएस समूह के संगठनों की ऐसे सभी मुद्दों पर निष्प्रभावी पहल और इनका निष्क्रिय एवं आत्ममुग्ध होना। ऐसे में दो ही विकल्प बचते हैं। देशहित में सरकार ऐसे हर मुद्दे पर जनमानस में एक व्यापक समर्थन तैयार करे। वहीं प्रत्येक मसले पर पूरी तैयारी के साथ आए तथा बिना दबाव के इसे लागू करें और अपने निर्णयों पर बनी रहे।

क्या केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार भंग न कर मौक़ा गँवा दिया

क्या केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को भंग न करके एक सुनहरा मौक़ा गँवा दिया? यह सवाल वाजिब है और इसके जवाब में कई पहलू शामिल हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए केंद्र सरकार का कोई भी फैसला बेहद पेचीदा और संवेदनशील माना जाएगा। एक तरफ़, अगर पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति काबू से बाहर होना साबित होता है तो सरकार को भंग करना एक सही कदम माना जाएगा पर मौजूदा हालात में यह कदम ना उठाना केंद्र की सूझ-बूझ और संविधान के प्रति सम्मान भी दर्शाता है। इस फैसले में सही या ग़लत का फैसला करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें न सिर्फ़ संवैधानिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ़ सियासी लाभ उठाने के बजाय पूरे मसले को बारीकी से देखना और समझना जरूरी होता है। इस नाजुक मौक़े पर केंद्र ने एक सधा हुआ फैसला लिया है या कोई मौक़ा चूक गया, यह वक़्त ही बताएगा। कोलकाता रेप कांड ने देशभर में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है, और पश्चिम बंगाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग हो रही है। ममता सरकार पर कानून-व्यवस्था की अनदेखी, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की नीति अपनाने के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार ममता सरकार की आलोचना की है, लेकिन इसके बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं हुआ है। ममता सरकार का रवैया ऐसा प्रतीत होता है मानो वह भारत के संवैधानिक दायरे से बाहर हो। अदालतों ने ममता सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय भर्ती घोटाले और शिक्षक भर्ती घोटाले को बड़ी सीजिश का हिस्सा माना है। इसके अलावा, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की बिना यूपीएससी की अनुमति के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की याचिका भी खारिज कर दी। रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की एनआईए से जांच कराने के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में %द

केरल स्टोरी% पर लगे बैन को भी हटा दिया और ममता सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि जब फिल्म पूरे देश में चल सकती है, तो बंगाल में क्या समस्या है? कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। कोलकाता के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसमें पुलिस और आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि इस जघन्य अपराध को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को सरकार और कोलकाता पुलिस की कड़ी आलोचना की, खासकर तब जब आरोपी संजय राॅय की बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर पाई गई। अदालत ने सवाल उठाया कि पुलिस की गाड़ी आरोपी के पास कैसे पहुंची और इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस कांड में सत्तारूढ़ टीएमसी के दो विधायकों के परिजन व कालेज का स्ट्राफ़ भी शामिल हैं, जिन्हें बचाने में ही पुलिस लगी है। पुलिस के शीर्ष अधिकारियों तक की भूमिका इस केस में संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। देरी से एफआईआर दर्ज करना और क्राइम सीन की ठीक से घेराबंदी न करना पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। इस घटना के बाद कोलकाता में हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई निरह्त्ये प्रदर्शनकारी घायल हुए। यह मामला सिर्फ एक आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठता है। ममता सरकार की निष्क्रियता और पुलिस की भूमिका ने राज्य में सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर जनता का विश्वास कमजोर कर दिया है। राज्य सरकार को भंग करने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियों प्रमुख होती हैं, उनमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, तत्संबंधी राज्यपाल की

रिपोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने या संवैधानिक संस्थाओं को संचालित करने में पूरी तरह असफल दिख रही है। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकते हैं, और राष्ट्रपति शासन का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के तहत संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप लागू किया जा सकता है। ममता सरकार भूल रही है कि बहुमत का मतलब संवैधानिक व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होता। कानून को अपनी सुविधा के लिए नहीं बदला जा सकता। विपक्षी दल ममता सरकार के भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर अदालतों की आलोचना के बावजूद चुप हैं। जब तक वे तुष्टिकरण की नीति छोड़कर सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करेंगे, मतदाताओं का विश्वास पाना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल सरकार को भंग न करने का निर्णय जटिल और संवेदनशील है, जिसमें कई संवैधानिक, राजनीतिक, और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। राज्य सरकार को भंग करना एक गंभीर कदम होता है, जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में उठाया जाना चाहिए, जैसे कानून और व्यवस्था की विफलता या सांप्रदायिक हिंसा। हालाँकि, इस निर्णय के पक्ष में तर्क दिए गए हैं कि संविधान का सम्मान बनाए रखना और राज्य में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। इस निर्णय को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा जा सकता है, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। लोग-यह कह सकते हैं कि इसके बजाय, केंद्र सरकार ने कानून और व्यवस्था के अन्य सुधारात्मक उपायों पर ध्यान देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल सरकार भंग करने से एक और तो भाजपा सरकार को राजनीतिक लाभ तो होगा ही पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने से न सिर्फ़ देश में यह मैसेज जाएगा कि हर राज्य को अपने यहाँ क़ानून व्यवस्था प्रभावी रखनी होगी। अपराधियों और उनको प्रश्रय दे रहे नेताओं को भी उन पर कड़ी कार्यवाही का डर रहेगा। वहाँ क़ानून व संवैधानिक व्यवस्था

ठीक की जा सकेगी और धार्मिक उन्माद पर बेहतर नियंत्रण रख आम जनता को बेहतर सुखा दिलाई जा सकेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में बंगलादेश शोक से आ रहे घुसपैठियों और आतंकियों को रोकने में मदद मिलेगी , और सीमा पर निगरानी में स्थानीय असहयोग पर बेहतर लगाम लगाई जा सकेगी।और वहाँ की तमाम परिस्थितियों को देख बंगाल में राज्य सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाना देश हित में अपेक्षाकृत बेहतर लगता है। कोलकाता रेप की इस घटना पर देशव्यापी आक्रोश का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा ऋस्तब्ध और व्यथित% राष्ट्रपति ने कहा कि %कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। इस घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया है राष्ट्र का आक्रोशित होना निश्चित है, और मैं भी आक्रोशित हूँ और भयभीत भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर गुस्सा व दुख जाहिर करने के साथ ही इस पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हुए बुधवार को कहा कि बस! बहुत हो चुका।इसके इस कथन को पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का क्या होगा फ़ौरी तौर पर यह अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यह निर्णय अभी भविष्य के गर्भ में है। पर यदि बंगाल सरकार और पुलिस इस प्रकरण में दोषपूर्ण कार्यवाही करती है तो केंद्र सरकार को ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए कि दोष पाए जाने पर दोषी भले ही बड़ा से बड़ा नेता, पुलिस का अधिकारी या रसुखदार ही क्यों न हो, उनको कठोरतम सजा मिले ताकि देश में क़ानून का इक़बाल बुलंद हो और यह दूसरों के लिये नज़ीर बन सके। (राजीव खन्) (लेखक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विशेषज्ञ एवं नक्सल मामलों के जानकार हैं एवं इंडियन कॉंसिल आफ प्रेस की छत्रीसगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं)

झापन ना लेने से नाराज जिलाध्यक्ष ने मंत्री पर कसा तंज

कहा कि कद बड़ा पर दिल छोटा है - मानसिंह कुशवाहा

आदित्य द्विवेदी । सिटी चीफ । भिण्ड, जिले में बिगडती व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार भिंड जिले के सुभाष तिराहे पर मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग कैबिनेट मंत्री व जिला भिण्ड प्रभारी प्रहलाद पटेल का घेराव करते हुए काफिले को रोककर जिला कांग्रेस कमटी जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपना चाहा तो मंत्री जी ने अहंकार वश जनता से जुड़ी मांगो वाला ज्ञापन पत्र नहीं लिया । कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कहा ,खनिज विभाग की मिलीभगत से जिले में अवैध रेत उखलन एवं परिवहन हो रहा है,जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट है,जिले में आमजनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है । श्री कुशवाहा ने कहा कि जिले की बिगडती हुई व्यवस्थाओं के संबंध में जब यहां के प्रशासन को बताया जाता है,तो वह इसे अनदेखा कर देते हैं । उन्होंने कहा कुल मिलाकर भिंड जिले में अधरे नगरी चौपट राजा जैसा हाल हो चुका है । यहां आमजनता की बात को देखने- सुनने वाला कोई नहीं है । श्री कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिले के नवनिर्युक्त प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को जनमसस्याओं के निराकरण कराने के लिए एक ज्ञापन पत्र देना चाहा तो अहंकार में डूबे प्रभारी मंत्री जी ने जनता से जुड़ी मांगो वाला ज्ञापन पत्र नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मंत्री जी अहंकार में इतने डूबे हुए हैं,तथा तंज करते हुए कहा कि मंत्री जी का कद बड़ा है

पर दिल बहुत ही छोटा है । श्री कुशवाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहा तो मंत्री जी ने ज्ञापन नहीं लिया निश्चित तौर पर यह भिण्ड जिले की समूची जनता का अपमान है, कांग्रेस पार्टी आमजन का अपमान बदार्शत नहीं करेगी, समय आने पर बीजेपी के अहंकार में डूबे हुए मंत्री और नेताओं को जनता सबक सिखाएगी

जनता से जुड़ी मांगो पर कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्ष करती रहेगी, और जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे । कांग्रेस द्वारा जनता की ओर से ज्ञापन पत्र में मुख्य मांगे थी -

(1) भिण्ड जिले में खनिज विभाग के द्वारा रिद्धि सिद्धि कंपनी को जस रेत डंप को उठाने की अनुमति प्रदान की गयी थी जबकि कंपनी द्वारा रेत डंप से ना उठाकर एनजीटी के रोक के बाद भी नदियों में से अवैध उत्खनन किया जा रहा है तथा कंपनी द्वारा डंप से 5 किलोमीटर दूर अवैध वसूली करने का कार्य किया जा रहा है ।

(2) जिले भर में विधुत व्यवस्था बुरी तरीके के चरमराई हुई है, जिले भर में अनुमानित बिल व मेटेनैस के नाम पर घंटो कटौती करने का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोका जाये ।

(3) अटेर क्षेत्र के ग्राम मीसा में मुख्य मार्ग पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने के कारण छोटे - छोटे मासूम बच्चे स्कूल तक नही जा पा रहे जिसकी शिकायत लगातार 2 महीने से ग्रामीणो द्वारा कलेक्टर भिण्ड को अवगत करा चुके उसके बाद भी ग्रामीणो की समस्या का

समाधान नहीं हो रहा है।

(4) आवादा गोवंश के कारण सैकड़ों एक्सीडेंट हो जाते हैं, भिण्ड - इटावा नेशनल हाइवे मार्ग पर कई घरों ने अपने चिरागों को खो दिया जबकि कमलनाथ सरकार में बनाई गयी गोशालाये बंद पड़ी हैं, जिन्हें संचालित कराया जाये जिससे गौ माता की भी रक्षा हो सके और एक्सीडेंट पर भी अंकुश लग सके।

(5) जिले भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चौपट हैं, भिण्ड जिला पहले से डाक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जो डाक्टर हैं, वह भी ड्यूटी टाइम पर नदारद रहते हैं तथा गोहद अस्पताल में खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म देने जैसी घटना तथा गोहद सामुदायिक केंद्र में इलाज के अभाव में विधायक के भाई की मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद विषय है।

ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, जिला संगठन मंत्री इराशद अहमद, जिला मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, एड. अमर सिंह शान्क्य, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह भदौरिया, किसान कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया, जिला मंत्री चंद्रभान सिंह कुशवाहा, एड. हरनारायण शर्मा, पार्षद आदेश अरेले रानू, जिला सचिव राजेंद्र सिंह परिहार, जिला महामंत्री विवेक पचौरी, अमित कुशवाहा, प्रमोद कुशवाहा, पिंकी उच्चाडिया, रामबरन सिंह कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह चौहान, नीरज सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

शिक्षा का बेहतर केंद्र बनेगा, हमारा यह लालबर्सा - श्रीमती अनुभा

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण



लालकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ । लालबारी, मुझे आप बिल्कुल ये अपेक्षा रखिए कि मैं निस्वार्थ भाव से हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मेरी सामर्थ्य होगी जो भी मेरी क्षमता होगी संपूर्ण योजना के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप सभी से मैं यह कहना चाहता हूँ जो स्पेन आप लोगों ने हमें दिया है जो मैं मान सम्मान दिया है इसमें लौटा तो नहीं सकते किसी भी कोमत पर नहीं लौटा सकते इतना जरूर है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास कर सकते हैं आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर सकते हैं इसी कोशिश में हम सबको चलना है सबको साथ लेकर काम करना है जो हमारा उत्कृष्ट विद्यालय है वह सीएम राजू बनने वाला है स्कूल की बिल्डिंग भी बनना है शिक्षा का बेहतर केंद्र बनेगा हमारा यह लालबारी ऐसी मुझे उम्मीद है उक्त बातें बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे द्वारा पैथा रोपण कार्यक्रम के दौरान कही गईं, वहीं नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांढरवाणी के द्वारा सीएम राजू शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर विद्यालय में एक पेड़ को के नाम अभियान के तहत 28 अगस्त दिन बुधवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अनुभा मुंजारे विधायक बालाघाट, श्री डुलेन्द्र ठाकरे मुन्ना भैया सभापति जिला



तथा छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना कि गई, फिर अतिथियों के उद्गार प्रारंभ हुए जिसमें बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की अनुभा मुंजारे ने अपने उद्घोष में आगे कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिए और सभी विद्यार्थी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए चिंतित हैं इसलिए सभी अधिक से अधिक पौधे लगाए ताकि क्षेत्र में हरियाली बनी रहे एवं शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। वहीं हमारी बेटी ने 97% बनाकर एक इतिहास रच दिया है यह बहुत सामान्य परिवार से आती है उसने स्कूल में शिक्षा अर्जित करने के बाद अगर यहां पर 97% लेकर आ रही है तो बहुत बड़ी बात है बहुत खुशी की बात है मैं बिटिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं जिस तरह से इन्होंने इतना परसेंट बनाया है आगे भी यह बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी जो भी जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगी। वहीं पाठरवारी सरपंच अनीश खान ने कहा कि शासन की योजना एक पेड़ मां के नाम के तहत अस्पताल रोड एवं स्कूल परिसर में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है और यह पेड़ बड़े होने के बाद छात्रों

प्रदान करेंगे एवं नगर सुंदर
लगेगा। वहीं सीएम राइज
शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर
विद्यालय के प्राचार्य एल सी
मानदत्तकर सर ने सभी अतिथियों
का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि जहां तक पार्टियों की बात है
यह शिक्षा का मंदिर है शिक्षा के
मंदिर में जो व्यक्ति अच्छा सोच
रखता है उसको किसी पार्टी से
मतलब नहीं होता वह सिर्फ शिक्षा
से मतलब होता है शिक्षा में जब
काम होगा देश का भविष्य अच्छा
बनेगा यह बच्चे हमारे कल के
भविष्य हैं सहित अन्य और भी
बातें करते हुए हुए सभी का
आभार व धन्यवाद प्रकट किये
तत्पश्चात कक्षा 9 वीं के 163
छात्र-छात्राओं को निःशुल्क
साइकिल वितरण किया गया है।
वहीं कार्यक्रम का सफल मंच
संचालन शिक्षक श्री सनत दुबे जी
द्वारा किया गया है। वहीं कार्यक्रम
में शिक्षक श्री एस के दुबे, एन
कटरे, खेमेन्द्र कटरे, पारस
रहांगडाले, अमन अवधिथा, सुनील
बाहेश्वर, एन के चौधरी, चन्द्रेश
तिरुवारि व शिक्षिकाओं में प्रमुख
रूप से श्रीमती सिमता तिरुवारि,
योगिता दुबे, पी दिक्षीत, पी
चौधरी, बनवाले मैडम, सरोज
हांगडाले, स्नेहलता रहांगडाले
सहित अन्य सभी लोग उपस्थित
रहे हैं।

शाजापुर में निकला चालीसवें का जुलूस

बड़ी संख्या में समाजजन रहे मौजूद

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ । शाजापुर, मोहरम के चालीस दिनों बाद मनाए जाने वाले चालीसवां पर्व पर अकीदतमंदों ने मन्तवें मांगी और फातेहा पदकर शोहदा-ए-कबला को याद किया। इसके बाद रात के समय एशिया के सबसे बड़े दुलदुल का जुलूस निकाला गया। इस दौरान हजारों अकीदतमंदों ने बड़े साहब दुलदुल के जुलूस में शामिल होकर या अली, या हुसैन की सदाएं बुलंद कीं। अकीदतमंदों के कांथे पर सवार दुलदुल को देररात इमाम बाड़ा में मकाम दिया गया और इस दौरान फातेहा पढ़ी गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।



शाजापुर के अस्पताल में चलाया गया रोक-टोक अभियान

एक दर्जन से अधिक लोगों से गूटका, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जप्त कर समझाईश दी गई

भगवान दास बैरागी ।
सिटी चीफ ।
शाजापुर, तंबाकू-गुटखा
खाकर यहां-वहां थूकते हुए
लोग गंदगी न फैला सकें
इसको लेकर मातृ-शिशु
स्वास्थ्य केंद्र में रोको-टोको
अभियान चलाया गया । केंद्र
के बाहर तैनात
सुरक्षाकर्मियों ने अभियान
के तहत गुरुवार को तंबाकू

लेकर केंद्र में प्रवेश करने से रोकने हेतु लोगों की चेकिंग की गई। इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों से गुटका, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जप्त किया गया। साथ ही समझाईश दी गई कि अगली बार तंबाकू-गुटखा लेकर नहीं आएँ, अन्यथा जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।



डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन जागरूकता अभियान के तहत पोलायकला में संवाद कार्यक्रम का आयोजन

सीएम राइज स्कूल में स्टूडेंट्स को कानूनी जानकारी दी गई

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ
शाजापुर, मिशन शक्ति अंतर्गत
डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ
वूमन के 100 दिवसीय जागरूकता
अभियान के 11वे सप्ताह में जिला
कार्यक्रम अधिकारी नीलम चौहान
के मार्गदर्शन में सीएम राईज स्कूल
पोलायकला में छात्र-छात्राओं के
साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन
किया गया । इस कार्यक्रम में बालक
एवं बालिकाओं को बाल विवाह
अधिनिषेध की जानकारी देते हुए
बताया गया कि बालिकाओं की 18

वर्ष एवं बालकों की 21 वर्ष उम्र से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति बालक-बालिका के साथ असुरक्षित स्पर्श करता है, अथवा कोई शारीरिक दुर्य्यवहार करता है या गलत फोटो, वीडियो लीक करने की धमकी देता है तो इस प्रकार के अपराधों के लिए उस व्यक्ति पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं साइबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वन स्टॉप प्रशासक द्वारा बच्चों को समझाईश दी गई कि इंटरनेट उपयोग ज्ञानवर्धन के लिए करें तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही वन स्टॉप सेंटर द्वारा



हिंसा पीड़ित किसी भी महिला या बालिका के प्रति हो रही हिंसा पर दी जाने वाली आश्रय, परामर्श, चिकित्सा, पुलिस तथा विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई एवं बताया गया कि हेल्पलाइन नंबर 181, 1098, 1930 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश कुमार शर्मा, स्टॉफ छतरसिंह वर्मा, कमल मंडल ओडिआ, दिनेश कलमोदिया, अर्चना शर्मा, बसंत बामनिया, संतोष कुलखंडिया, सुनील व्यास, विनोद मंडलोई, अरुण वर्मा, कौशल्या वर्मा, नेहा राठौर, जीवन वर्मा, परियोजना सुपरवाइजर शमरोज खान, श्रीमती माया मिरोट उपस्थित थीं।

राजापुर कलेक्टर ने कहा

छात्रावासों एवं आश्रमों की रिक्त सीट भरने के लिए छात्रावास अधीक्षक स्वयं प्रयास करें

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ । राजापुर, जिले के छात्रावासों एवं आश्रमों में रिक्त सीट्स भरने के लिए छात्रावास अधीक्षक स्वयं प्रयास करें। उक्त निर्देश कलेक्टर ऋजु बाफना ने गुरुवार को छात्रावासों एवं आश्रमों के अधीक्षकों की बैठक लेकर दिए। कलेक्टर बाफना ने छात्रावास अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए कि वे रिक्त सीटों को भरने के लिए स्वयं प्रयास करें। आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचों, जनप्रतिनिधियों, पटवारियों, जनपद पंचायतों के सीईओ, तहसीलदारों से मिलकर छात्रावासों की सीट्स भरने का प्रयास करें। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक सर्वेदनशीलता के साथ विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। छात्रावासों की व्यवस्थाएं सुधारे, बच्चों की समस्याओं का निराकरण करें



और विद्यार्थियों को दिए जाने वाला भोजन गुणवत्तायुक्त हो तथा प्रदाय सामग्री का उपयोग करें। नवीन प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता यदि ठीक नहीं है तो उसे वापिस करें। छात्रावासों में ग्रन्थालय विकसित करें। छात्रावासों में यदि

छोटी-छोटी मरम्मत की आवश्यकता हो या अन्य प्रकार की समस्याओं के संबंध में नोडल अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी जीएल गुवाटिया को अवगत कराएं। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षकों से कहा कि

सभी से अच्छे काम की अपेक्षा है। अच्छे कार्यों के लिए सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी जीएल गुवाटिया, जिला संयोजक मीना मण्डलोई सहित छात्रावास के अधीक्षक मौजूद थे।



गौरव सिंघल । सिटी चीफ । सहारनपुर । देवबंद, दून वैली स्कूल में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक व राजनीतिक विश्लेषक शान्तनु गुप्ता को छात्रों के लिये एक प्रेरणादायक सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता शान्तनु गुप्ता, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर अनुराग सिंघल तथा प्रधानाचार्या श्रीमती सीमा शर्मा ने मां सरस्वती जी के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन एवं दीप प्रवर्तित कर प्रेरणादायी सत्र का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के आरम्भ में अतिथियों का स्वागत सामूहिक

स्वागत गान, पुष्पगुच्छ व माल्यार्पण से किया गया। तत्पश्चात् अनुराग सिंघल ने अतिथि एवं मुख्य वक्ता शान्तनु गुप्ता का विशद परिचय कराकर सत्र के लिये आमंत्रित किया। मुख्य वक्ता शान्तनु गुप्ता ने भारतीयता पर जोर देते हुए विभिन्न उदाहरण देकर स्वयं को पहचानने पर जोर दिया तथा इतिहास में भारतीय योगदान का श्रेय विदेशी विद्वानों को दिये जाने पर विद्यार्थियों को प्रेरणादायी सत्र का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर अनुराग सिंघल ने

अपने उद्बोधन में छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ प्रयोगात्मक होने की अपील की और कहा कि स्किल आधारित शिक्षा ही आज के युग में सफलता की कुंजी है। स्कूल की प्रधानाचार्या श्रीमती सीमा शर्मा ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अभिनन्दन पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया और उनके प्रेरणादायक सत्र को विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का संचालन आराध्या, अफीफा तथा काव्या ने सफलतापूर्वक किया।

वैश्य समाज के स्वाभिमान को बरकरार रखने हेतु सभी को मिलकर चिंतन करना होगा

समाज में क्या-क्या विसंगतियां, कुरीतियाँ है उन्हें दूर करने हेतु कुछ बड़े फ़ैसले लेने होंगे : पूर्व मंत्री संजय गर्ग



गौरव सिंघल । सिटी चीफ । सहारनपुर, वैश्य समाज की एक बैठक सहारनपुर में पूर्व मंत्री संजय गर्ग के निवास स्थान पर हुई। जिसमें जिले के कोने-कोने से वैश्य अग्रवाल समाज के गणमान्य लोग पहुंचे। बैठक में पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने कहा वैश्य समाज के स्वाभिमान को बरकरार रखने हेतु सभी को मिलकर चिंतन करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में क्या-क्या विसंगतियां, कुरीतियाँ है उन्हें दूर करने हेतु कुछ बड़े फ़ैसले लेने होंगे। सभा की अध्यक्षता संरक्षक योगेश गुप्ता ने की। बैठक में मुख्य रूप से नकुड़ के चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता, पार्षद ज्योति

गुप्ता, पार्षद मयंक गर्ग, पार्षद अनिल गर्ग, गंगोह सभासद नीरज अग्रवाल, समन्वय समिति के अध्यक्ष पवन गोयल, महामंत्री रवि गुप्ता, रामलीला कमेटी के प्रधान विनय जिंदल, सौरव गर्ग, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रल, आई वी एफ के जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य महा समेलन के जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, चेतना मंच के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, भाजपा महानगर महासचिव शीतल बिश्नोई, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अनिल सिंघल, अमर गुप्ता, प्रमोद बंसल, अखिलेश मिश्रल, रामराजीव सिंघल, मोरगंज व्यापार मंडल के

अध्यक्ष अनुज अग्रवाल, सद्गौली से प्रदीप प्रधान, उसंड से सचिन गर्ग, सरसावा से महावीर गुप्ता, चिलकाना से हिमांशु गर्ग, गागलहेडी से महेश गुप्ता, नागल से अजय अग्रवाल, मोहित गोयल, नानौता से अरविंद अग्रवाल, सुनील मिश्रल, चोरी मंडी से प्रमोद गुप्ता, सुरेंद्र अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राजीव गुप्ता, रणखंडी से सतीश अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, नवीन सिंगल, मदन मोहन गुप्ता, अलंकार किशोर आदि सैकड़ों की संख्या में अग्र बंधु उपस्थित रहे। बैठक का संचालन व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नरेश गोयल ने किया।

कटनी में दादी - पोते के साथ हुई मारपीट के वायरल वीडियो पे लिया गया एक्शन

जीआरपी थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जीतू पटवारी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात



सुनील यादव । सिटी चीफ । कटनी, कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर एवं 19 अपराधों को घटित करने वाले शातिर बदमाश दीपक वंशकार के परिजनों के साथ पूछताछ के दौरान हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद रेल पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ही कटनी जीआरपी थाना प्रभारी समेत 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक रेल को सौंपी जा चुकी है। इस मामले में सुबह से ही जिले में इस मामले को लेकर पुलिस विभाग और जीआरपी विभाग में गहमा गमहमा का माहौल बना रहा और कटनी जिले में शाम के वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी जिले में पहुंच पीड़ित महिला से मुलाकात करने पहुंचे और उनसे बात की और पीड़ित परिजनों द्वारा जब जीआरपी थाना प्रभारी अरूणा वाहने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात रखी तो वह

तुरंत ही पीड़ित महिला और उनके 17 साल के नाती को लेकर रंगनाथ थाना पहुंचे जहां के वह निवासी थे और जीआरपी थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पर अड़ गए की जबतक मामला दर्ज नहीं होता वहां आमरण अनशन पर बैठ रहेंगे और आखिर कार 4 घंटे के बाद इस पूरे मामले में रंगनाथ नगर थाने में अरूणा वाहने ने अपने कटनी जिले के सोशल मीडिया whatsapp ग्रुप पर जिसमें मीडिया कर्मियों को विज्ञप्ति भेजने का काम किया जाता था उस पर इस वीडियो वायरल होने के मामले में टेक्स मैसेज कर बताया की यह वीडियो करीबन एक साल पुराना है और उनके केबिन में लगे सरकारी सीसीटीवी का वीडियो है और यह वीडियो की कॉपी लेकर कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उनसे 5 लाख रूपयों की मांग कर रहे थे और इस पूरे मामले को दबाने की बात कह रहे थे लेकिन वह नहीं मानी तो इस वीडियो को उन

मामले में खुद पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे और पीड़ित महिला के साथ थाने पहुंच जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराने पर अड़ गए और 4 घंटे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी किया। वही इस पूरे मामले में एक और अन्य मोड़ तब आया जब जीतू पटवारी कटनी जिले में आने वाले थे तभी जिस जीआरपी थाना प्रभारी अरूणा वाहने ने अपने कटनी जिले के सोशल मीडिया whatsapp ग्रुप पर जिसमें मीडिया कर्मियों को विज्ञप्ति भेजने का काम किया जाता था उस पर इस वीडियो वायरल होने के मामले में टेक्स मैसेज कर बताया की यह वीडियो करीबन एक साल पुराना है और उनके केबिन में लगे सरकारी सीसीटीवी का वीडियो है और यह वीडियो की कॉपी लेकर कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उनसे 5 लाख रूपयों की मांग कर रहे थे और इस पूरे मामले को दबाने की बात कह रहे थे लेकिन वह नहीं मानी तो इस वीडियो को उन



लोगो द्वारा वायरल करा दिया गया..इस मामले पर भी जब जीतू पटवारी ने कहा की जब यह वीडियो उनके पास पहुंचा तो वे सिर्फ दलित महिला के सात हुए मारपीट को लेकर झुंकाउंट पर डाल है, और इस वीडियो के माध्यम से जीआरपी थाना प्रभारी से वसूली की बात उनके पास नहीं आई है। वे सिर्फ महिला के साथ हुए मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे है। और यदि ऐसा हुआ है तो यह पुलिस का काम है जांच कराने का। और चार घंटे के बाद जब जीतू पटवारी मामला दर्ज कराने के लिए थाने में धरना दिए बैठे हुए थे तब पुलिस को इस पूरे मामले में मामला दर्ज कराना पड़ा।

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 119वीं जयंती पर नमन करते हुए उनकी याद में खेला गया मैत्री मैच

हॉकी खिलाड़ियों ने मेजर ध्यान चंद को भारत रत्न मिलने की मांग रखी

गुना। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त 2024 को 119वीं जयंती के शुभ अवसर पर संजय गांधी हॉकी स्टेडियम में मैत्री मैच खेलकर मनाई गई। मैत्री मैच से पूर्व अतिथियों द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ ही हॉकी खिलाड़ियों एवं नगर वासियों ने मेजर ध्यान चंद को भारत रत्न देने की सरकार से मांग उठाई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य

अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह सिकरवार, जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र रघुवंशी, भाजपा जिला मिडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, जिला हॉकी संघ के सचिव बृजेश दुबे सीनियर हॉकी खिलाड़ी मुरारी लाल शर्मा मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों द्वारा जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ कराया। ओर विजेता टीम को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष श्री सिकरवार ने कहा की

आज हांकी के जादूकर मेजन ध्यान चंद जी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हु। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में जन्मे ध्यानचंद की जयंती पर हर साल देश में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने तीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में उनके रहते हुए टीम ने कमाल किया था और स्वर्ण पदक जीतने में

सफलता पाई थी। उनकी गोल करने की क्षमता के आगे विपक्षी टीम बेबस नजर आती थी। वह सिर्फ दूसरे छोर से ध्यानचंद को देखते ही रह जाते थे। इस अवसर पर शक्ति सिंह अग्निवंशी, राजेंद्र जगताप, राकेश वैष्णव, किशन सिंह ठाकुर, शरद शर्मा, महबूब निसार खान, जितेंद्र अग्निवंशी, दुर्गेश सक्सेना सुनीता कवर, अखलाक खान सहित जिला हॉकी संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

सफलता पाई थी। उनकी गोल करने की क्षमता के आगे विपक्षी टीम बेबस नजर आती थी। वह सिर्फ दूसरे छोर से ध्यानचंद को देखते ही रह जाते थे। इस अवसर पर शक्ति सिंह अग्निवंशी, राजेंद्र जगताप, राकेश वैष्णव, किशन सिंह ठाकुर, शरद शर्मा, महबूब निसार खान, जितेंद्र अग्निवंशी, दुर्गेश सक्सेना सुनीता कवर, अखलाक खान सहित जिला हॉकी संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित रहे।



अस्पतालों में आने वाले अटेंडरों को पहचान पत्र जारी करें - मुख्य सचिव श्रीमती राणा

कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करें सतत् निरीक्षण

मंडला

मौसमी बीमारियों के उपचार की सभी व्यवस्थाएँ रहें सुचारु

मुख्य सचिव ने की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ और नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाए। सी.सी.टी.वी. कैमरों से न केवल अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही भी संभव हो सकेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य कर सकें। उन्होंने अस्पतालों में आने वाले अटेंडरों को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि अनधिकृत लोगों की आवाजाही पर रोक लग सके। मुख्य सचिव ने कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाइट व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय



और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने मंत्रालय वल्लभ भवन में उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनहितकारी योजनाओं और स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिलेवार वर्चुअल समीक्षा की। मुख्य सचिव ने मौसमी बीमारियों के दृष्टिगत शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में बीमारियों के उपचार की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत शेष बचे पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड अभियान चलाकर बनाने के निर्देश दिये। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिले। मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के विचरण को रोकने के लिये नगरीय विकास, पुलिस, ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग

आपसी समन्वय से कार्य करें। साथ ही इन पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। मंडला एनआईसी कक्ष से बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा, एसपी रजत सकलेचा, एडीएम राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम जन-मन महा अभियान के लक्ष्यों को समय पर पूरा करें मुख्य सचिव श्रीमती राणा ने कहा कि पीएम जन-मन महा अभियान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। उन्होंने अभियान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम जन-मन महा अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।

अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नगरीय

विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिये कि संबंधित नगरीय निकाय डीपीआर को जल्द से जल्द तैयार करें और कार्यों को समय से पूरा करें। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, हरित क्षेत्र विकास और शहरी परिवहन के कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और इन प्रोजेक्ट्स को समय पर तय गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

राजस्व महाअभियान की समीक्षा मुख्य सचिव ने प्रदेश में संचालित राजस्व महाअभियान की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने बारिश की स्थिति पर सतत निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार राहत शिविरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभाग समन्वित और तैयार रहें। मुख्य सचिव ने वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की निर्धारित प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करने के कलेक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देने और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का अभियान चलाने के निर्देश दिए।

अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के साथ हों सुरक्षा के पुरख्ता प्रबंध : मुख्य सचिव

कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करें सतत् निरीक्षण

जबलपुर

मौसमी बीमारियों के उपचार की सभी व्यवस्थाएँ रहें सुचारु

मुख्य सचिव ने की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की समीक्षा और दिये निर्देश

मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा ने प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ और नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाए। सी.सी.टी.वी. कैमरों से न केवल अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्यवाही भी संभव हो सकेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य कर सकें। उन्होंने अस्पतालों में आने वाले अटेंडरों को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिये, ताकि अनधिकृत लोगों की आवाजाही पर रोक लग सके। मुख्य सचिव ने कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाइट व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने मंत्रालय वल्लभ भवन में



उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनहितकारी योजनाओं और स्वास्थ्य-सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिये कि संबंधित नगरीय निकाय डीपीआर को जल्द से जल्द तैयार करें और कार्यों को समय से पूरा करें। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, हरित क्षेत्र विकास और शहरी परिवहन के कार्यों की स्थिति की समीक्षा की और इन प्रोजेक्ट्स को समय पर और तय गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये।

जल जीवन मिशन के कार्य गुणवत्तापूर्ण हों मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के विचरण को रोकने के लिये नगरीय विकास, पुलिस, ग्रामीण विकास और पशुपालन विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। साथ ही इन पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें।

राजस्व महाअभियान की समीक्षा मुख्य सचिव ने प्रदेश में संचालित राजस्व

महाअभियान-2 की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने बारिश की स्थिति पर सतत निगरानी रखने और जरूरत के अनुसार राहत शिविरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि संभावित आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभाग समन्वित और तैयार रहें।

निवेश प्रोत्साहन केंद्रों की स्थापना मुख्य सचिव ने बताया कि ग्वालियर - चंबल संभाग के सभी जिलों में निवेश प्रोत्साहन केंद्रों का शुभारंभ किया जा चुका है। शेष जिलों में भी प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र प्रारंभ कर नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएँ। मुख्य सचिव ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की निर्धारित प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये। उन्होंने पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ देने और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने अभियान चलाने के निर्देश दिये। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री संदीप यादव सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम विश्वकर्म योजना का जिले में बेहतर क्रियान्वयन करें सुनिश्चित-

योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराएं रोजगार मुहैया- कलेक्टर ने किया पीएम विश्वकर्म योजना के प्रगति की समीक्षा

अनूपपुर

कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा है कि सपीएम विश्वकर्म योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जिले में पीएम विश्वकर्म योजना का सभी संबंधित अधिकारी बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। जिले के लोगों को चिन्हित कर प्रशिक्षण दिलाएँ तथा योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाएँ। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ट्रेनिंग भी कराएँ। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित बैठक में पीएम विश्वकर्म योजना के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के तहत 18 पारंपरिक



व्यापारों को लाभ देना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम व्याज में तीन लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है, इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके लिए रोजाना 500 रुपये का स्टिपेंड दिया जाता है। साथ ही टूल किट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाते हैं। बैठक में कलेक्टर ने पीएम विश्वकर्म योजना के अंतर्गत महाप्रबंधक जिला एवं व्यापार उद्योग केंद्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय

मॉनिटरिंग समिति गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति में अग्रणी जिला प्रबंधक, आईटीआई प्राचार्य, डीपीएम आजीविका मिशन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग के अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी सदस्य होंगे, जो योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयास करेंगे तथा योजना के प्रगति का आंकलन कर कलेक्टर कार्यालय को जानकारी प्रेषित करेंगे। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत तुलसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी

जोड़ा जाए तथा जो योजना के अंतर्गत पात्र हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण दिलाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के लोगों के अंदर कला एवं स्किल है, उसे डेवलप एवं प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में गोंड पेंटिंग, बीजापुरी शिल्प काष्ठ सहित अन्य विभिन्न कला जो अनूपपुर में विख्यात है, उनको योजना अंतर्गत प्रोत्साहित करने के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यहां की विशेष कलाएँ हैं, उन्हें इस योजना के माध्यम से और आगे बढ़ाई जाए तथा उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें। इस दिशा में अधिकारी बेहतर कार्य करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री आर.एस. डाबर, जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त सुश्री सरिता नायक, एनआरएलएम के डीपीएम श्री शशांक प्रताप सिंह, सहायक संचालक उद्यान श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जिला अग्रणी प्रबंधक श्री अजीत नम्बियार सहित जिले के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मैदानी स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो - मंत्री श्री प्रहलाद

गिण्ड

शासन की योजनाओ का लाभ सभी पात्र जरूरतमंद तक पहुंचना सुनिश्चित करे

प्रभारी मंत्री श्री पटेल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई जिले के प्रभारी मंत्री तथा मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार भिण्ड में आयोजित की गई। इस दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, नवरिया, विधायक भिण्ड श्री नेन्द्र सिंह कुशवाह, विधायक लहरा श्री अम्बरीश शर्मा, कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव, एसपी डॉ अमित यादव सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित समस्त अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जिले में वर्तमान में प्रगतिरत सड़कों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले की कौन सी विधानसभा में कितने किलोमीटर की सड़कें हैं, कितने



प्रतिशत कार्य पूर्ण के संबंध में जानकारी ली। पहले चरण की सड़कों, उनपर पर बनाई गई पुलिया, शासन को भेजे गए प्रस्ताव के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले में सड़कों पर चल रहे मंटेनेंस कार्य के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की। जिले में कुल आवासों की जानकारी लेते हुए कहा कि ऐसे कितने आवास हैं जो धीमी गति से बना रहे हैं, ऐसे कितने आवास हैं जिनमें अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है और उनसे राशि वसूली, के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि जिन आवासों में काम नहीं किया गया है उनसे वसूली की कार्यवाई की जाए। साथ ही ऐसे आवास हितग्राही जो अपात्र श्रेणी में हैं उनसे रिकवरी की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना

अंतर्गत गोहद के ग्राम डोंग, गुरीखा, टेटोन में दिए गए आवास, जन धन बैंक खाता, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त सीईओ जनपद पंचायत से जनपद क्षेत्र एवं पंचायतों में किए गए पौधारोपण कार्य, पौधों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने विभागों के माध्यम से किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रगति समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों को मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित आवश्यक निर्देश देते हुए कहा की शासन की योजनाओ का लाभ सभी जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को दिया जाए।



अलीराजपुर मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा की अध्यक्षता में अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था ,राजस्व महाअभियान, पीएम जनमन,अमृत 2.0,जल जीवन मिशन एवं निराश्रित मेवेशियों के लिए 15 दिन का विशेष अभियान आदि विषयों पर समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर वीसी के माध्यम से सम्मिलत हुए।



सतना गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में जिला पशु कल्याण समिति/जिला गोपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति तथा जिला पशु कूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

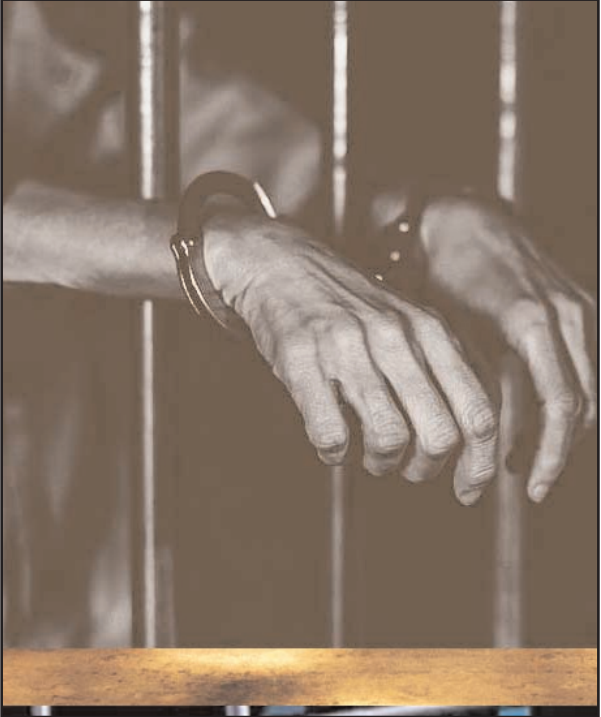
कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने निर्माणाधीन सीएम राईज विद्यालय भवन का निरीक्षण किया

डिंडोरी कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने आज गुरुवार को निर्माणाधीन सीएम राईज विद्यालय भवन का निरीक्षण किया। नरिया में आठ ब्लॉक का सीएम राईज विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिलामें प्रयोगशाला, कक्षाएं, खेल प्रांगण आदि सम्मिलित हैं। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने उक्त भवन का निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा लिया। जिसमें बताया गया कि भवन का संरचनात्मक कार्य हो चुका है। प्लास्टर और प्लोरिंग का कार्य चल रहा है। कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता, लैब रिपोर्ट, बाउंड्री निर्माण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन के लिए स्वीकृत लैब रिपोर्ट का सतत रूप से अवलोकन कराएँ और निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूरा करें। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत सुश्री विमलेश सिंह सहित अन्य विभागों अधिकारी मौजूद रहे।



20 देशों में 286 यौन शोषण के केस में पाक मूल के शख्स को 17 साल की जेल

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मूल के शख्स की एक धिनौनी करतूत सामने आई है। यहां की एक अदालत ने इसे सबसे जघन्य ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामला बताते हुए पाक मूल के व्यक्ति को 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस शख्स ने देश-विदेश में सैकड़ों पीड़ितों को निशाना बनाया था। वह खुद को एक 15 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताकर लोगों को गुमराह करता था जिसके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। 29 साल के मुहम्मद जैन उल अब्दिन रशीद ने 119 आरोपों में दोषी होने की बात कबूली है जो यूके, यूएस, जापान और फ्रांस सहित 20 देशों के 286 लोगों से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने दो-तिहाई 16 साल से कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाया था। पर्थ की एक अदालत में बताया गया कि रशीद ने उन बच्चियों को उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें उनके परिवार वालों को भेजने की धमकी देकर उनके साथ शोषण करता रहा। उसने एक यूट्यूब स्टार होने का नाटक किया और बच्चों को पालतू जानवरों या दूसरे छोटे भाई-बहनों के साथ सेक्सुअल एक्ट करने के लिए ब्लैकमेल किया। जज अम्मांड बरोज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले मुझे



ऐसा कोई मामला नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि यह हद है कि रशीद ने अपने साथियों के साथ पीड़ितों के साथ धिनौना काम किया और लोगों को बच्चों द्वारा किए जा रहे सेक्सुअल एक्ट की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए बुलाया करता था।

पहले से सजा काट रहा है आरोपी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के सहायक आयुक्त डेविड मैकलीन ने बताया, इस शख्स ने जो काम

किया है वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे भयानक सेक्सटॉर्शन मामलों में से एक है। इस प्रकार का ऑनलाइन शोषण और दुर्व्यवहार भयानक है और यह किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। रशीद पहले से ही एक अलग अपराध के लिए पांच साल की सजा काट रहा है। इससे पहले उसने दो मौकों पर अपनी कार में एक नाबालिग का यौन शोषण किया था।

गुजरात में बाढ़ से सड़के जलमग्न, कमर तक पानी, गाड़ियां डूबीं, 28 की मौत

अहमदाबाद। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ से जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात सरकार के अनुसार, मोरबी, वडोदरा, भरूच, जामनगर, अरावली, पंचमहल, द्वारका और डांग जिलों में कई लोगों की मौत हुई है। आणंद में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि अहमदाबाद में चार की जान चली गई। इसके अलावा गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, दाहोद और सुरेंद्रनगर जिलों में दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में वे सात लोग भी शामिल हैं, जो मोरबी जिले में धवना गांव के पास एक उफनती नदी को पार करते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली के बह जाने के बाद लापता हो गए थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 18,000 लोगों को निकाला गया है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट और 22 जिलों के लिए येलो



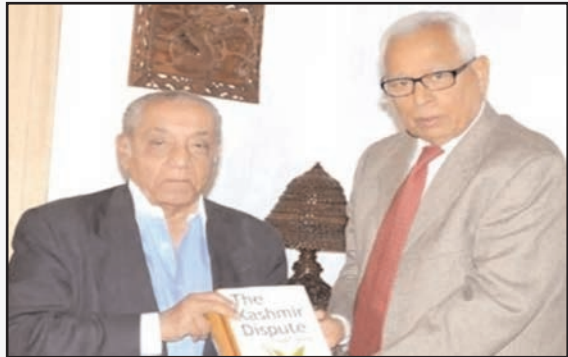
अलर्ट जारी किया है।

राज्य के 18 जिले बाढ़ की चपेट गुजरात के 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 8,400 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातकर स्थिति का जायजा लिया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं, भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर नॉर्थ से भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा भी बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने निकलीं। रिवाबा जडेजा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने सोशल

मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में वे कमर तक बाढ़ के पानी से भरी गलियों में घूमती दिखीं और लोगों से मुलाकात भी की। **सेना चला रही बचाव कार्य** मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अहमदाबाद, वडोदरा, जूनागढ़ समेत कई जिलों में भी भारी बारिश हुई। अधिकारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है।

अहमदाबाद, राजकोट, बोटान, आणंद, खेड़ा, महिसागर, कराच और मोरबी में प्राइमरी-सेकंडरी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। **रेलवे लाइन जलमग्न, कई ट्रेनें रद्द** पश्चिम रेलवे ने बताया कि बारिश के कारण सड़के और रेलवे लाइन जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात और रेलगाड़ियों की आवाजाही भी बाधित हुई। मुंबई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनें रद्द कर दी गईं और 10 अन्य ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गईं। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य में 140 जलाशय और बांध तथा 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत बलों के अलावा सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल को बचाव और राहत कार्य के लिए बुलाया गया है। गुजरात में लगातार बारिश के बाद बाढ़ के बीच, जामनगर में पडाना पाटिया को चंगा पाटिया से जोड़ने वाली सड़क को यातायात को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। सर पीएन रोड पर बने एक छोटे पुल का एक हिस्सा भी बाढ़ के कारण बह गया है, जिससे यात्रियों का आवागमन प्रभावित हुआ है।

मशहूर राजनीतिक टिप्पणीकार, वकील और लेखक एजी नूरानी का निधन



मुंबई। मशहूर राजनीतिक टिप्पणीकार, वकील और लेखक एजी नूरानी का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें चर्चित द कश्मीर क्लेशचन भी शामिल है। वे संवैधानिक मामलों के बड़े कानूनी जानकार थे। संवैधानिक मामलों पर विशेषज्ञता की वजह से विद्वान जगत में उन्हें काफी सम्मान प्राप्त था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक प्रैक्टिस की थी। वे लंबे अकादमिक और पत्रकारिता करियर के लिए भी मशहूर रहे हैं। वे कई अखबारों में नियमित कॉलम भी लिखा करते थे। उन्होंने कई सेमिनारों में कई पेपर पेश किए हैं। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनके निधन पर दुःख जताया है और अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, विद्वानों के बीच एक दिग्गज ए जी नूरानी का निधन हो गया है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, संविधान से लेकर कश्मीर, चीन और यहां तक कि अच्छे खाने की सराहना करने की कला भी। अल्लाह उन्हें मगफिरत अता करे। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक्स पर लिखा, ए जी नूरानी साहब के निधन के बारे में सुनकर दुःख हुआ। नूरानी साहब एक स्कॉलर, एक कुशल वकील और एक विद्वान राजनीतिक टिप्पणीकार थे। उन्होंने कानून के मामलों और कश्मीर, आरएसएस और संविधान जैसे विषयों पर विस्तार से लिखा। अल्लाह उन्हें जन्नत में सबसे ऊंचा स्थान दे।

हरियाणा चुनाव की तारीखों में नहीं होगा बदलाव, 1 अक्टूबर को ही मतदान



नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। चुनाव आयोग के हवाले से सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर को ही मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि, आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इस बीच, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने अधिकारियों को पूर्व निर्धारित चुनावी कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और राज्य की सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव की तारीख बदलने के लिए आयोग को चिट्ठी लिखी थी। दोनों दलों ने छुट्टियों का हवाला देते हुए मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश आयोग से की थी। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रधान महासचिव अभय सिंह चोटाला ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एक अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने चुनाव आयुक्त को ध्यान दिलाते हुये लिखा था कि मतदान के दिन से पहले दो राजपत्रित छुट्टियां हैं, यानी 28 सितंबर को शनिवार और 29 सितंबर को रविवार है। एक अक्टूबर को भी मतदान अवकाश है और उसके बाद दो राजपत्रित छुट्टियां होगी। यानी दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और तीन अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती है। उन्होंने आगे लिखा कि चूंकि लोग आमतौर पर लंबे सप्ताहांत पर छुट्टियों पर जाते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा। मत प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 15 से 20 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है। इसके अलावा चुनाव के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ चुनाव की तैयारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उत्तरप्रदेश के बहराइच के 50 से अधिक गांवों में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों ने दहशत के मामले में बाघ व तेंदुओं को भी पीछे छोड़ा

यूपी के सिस्टम को नचा रहे खूनी भेड़िये...

बहराइच। उत्तरप्रदेश के बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों ने दहशत के मामले में बाघ व तेंदुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल जनवरी माह से अब तक तेंदुओं ने चार को निवाला और 17 लोगों को घायल किया है, लेकिन भेड़ियों ने नौ लोगों को निवाला तो वहीं 35 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। 17 जुलाई से 28 अगस्त के बीच ही सात बच्चों को मारा तो 25 को घायल कर दिया। महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में तबाही मचाने के साथ ही अब भेड़िया खैरीघाट क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए हैं। दहशत का आलम यह है कि हरदी व खैरीघाट से सटे अन्य क्षेत्रों के ग्रामीणों की भी नौद हराम हो गई है। अभी तक के हालात को देखें तो मात्र चार से छह भेड़िये ही पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। 17 जुलाई को हुए हमले के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस व वन विभाग लगातार भेड़ियों को पकड़ने व हमले रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। मुख्य वन संरक्षक व वन राज्यमंत्री ने सिर्फ तीन भेड़ियों के होने का दावा किया है। यही तीन भेड़िये बीते 41 दिनों से 32 राजस्व टीमों, 200 से अधिक पुलिसकर्मियों, मंडलीय समेत 10 से अधिक वन टीमों को चकमा दे रहे हैं और लगातार स्थान परिवर्तन कर उन्हें नचा रहे हैं।

मादा भेड़िया के पकड़े जाने के बाद बड़े हमले वन विभाग ने तीन अगस्त को एक मादा भेड़िया को पकड़ा था। वन प्रभाग लाते समय उसकी मौत हो गई। इसके बाद मादा भेड़िया को भी वन विभाग ने पकड़ा, लेकिन हमलों में कोई कमी नहीं आई। हमले बढ़ते ही गए। इसके बाद ग्रामीण झुंड की मुखिया के मौत के बाद बदला स्वरूप हमला करने की भी बात कह रहे हैं।

स्पेशल टास्क फोर्स, ड्रोन-ट्रेप कमेरे भी



असहाय भेड़ियों को पकड़ने के लिए बाराबंकी के डीएफओ आकाशदीप बघावन को स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में बुलाया गया। इसके बाद भी भेड़ियों ने रीता देवी, अयांश को निवाला बना लिया और तीन मासूम सहित चार को घायल किया। यही नहीं, भेड़ियों के आगे वन विभाग की ओर से लगाए गए 10 ट्रैप कैमरे, जाल, पिंजरा व ड्रोन कैमरे भी असहाय नजर आ रहे हैं। **बच्चों की पढ़ाई तो किसानों की खेती भी चौपट** महसी तहसील के गांवों में दहशत का आलम यह है कि किसान छुट्टा मवेशियों से फसल रखवाली के लिए खेत नहीं जा रहे हैं। इससे उनकी फसल मवेशी चट कर रहे हैं। वहीं नौनिहालों की पढ़ाई भी बाधित है। भेड़ियों के डर से अधिकतर अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। इस बीच जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, तो उनके अभिभावक साथ रह रहे हैं। **हांका व ड्रोन की आवाज से दिन तो टार्च की रोशनी से कटती रात** भेड़ियों का डर इस कदर व्याप्त है कि लोगों की सुबह हांका व ड्रोन कैमरों की आवाज सुनने से हो रही। वहीं रात भी टार्च की दृधिया रोशनी व हांके की आवाज के बीच जागकर बीत रही है। खूंखार भेड़ियों की दहशत का आलम यह है

कि बच्चे दिन के समय भी खेलते नजर नहीं आते हैं। **बदले की प्रवृत्ति व कुनबे पर हमले पर हिंसक होता है भेड़िया** कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सेवानिवृत्त डीएफओ ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि भेड़िया काफी चालाक और बदले की भावना वाला जानवर है। नदी के कछार में मांद बनाकर स्थानीय जंतुओं का शिकार करता है। मनुष्यों पर बहुत की कम हमले करता है, लेकिन इसमें बदले की प्रबल भावना होती है। उन्होंने बताया कि इनके बच्चे को मारने पर कुनबे का नर या मादा मुखिया उग्र होकर हमले करता है। हरदी में भी हो सकता है किसी ने इनके बच्चे को छति पहुंचाई हो, जिसके बाद से सभी बदले की भावना से हमले कर रहे हों। **ट्रैपिंग कैमरे से पता लगाना या मारना बेहतर उपाय** सेवानिवृत्त डीएफओ ज्ञान प्रकाश सिंह ने बताया कि सबसे पहले कैमरा ट्रैपिंग से हमलावर भेड़िये का पता लगाना होगा। इसके बाद उसे पकड़ना या मुख्य वन संरक्षक से आदेश लेकर हमलावर भेड़िये को मारना बेहतर उपाय होगा, तभी हमलों में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि 1997 में जौपुर के प्रतापगढ़ व बलरामपुर जिले में

शिवाजी की प्रतिमा गिरने की जांच के लिए तकनीकी समिति गठित

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने तटीय कॉकण के मालवन में सतरहवीं सदी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को मूर्ति गिरने के कारणों की जांच और नई प्रतिमा के निर्माण के लिए एक तकनीकी समिति गठित कर दी है। समिति में इंजीनियर्स, आईआईटी विशेषज्ञ और नौसेना के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल, आधी रात के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक एक विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कहा गया कि सरकार ने योद्धा राजा की प्रतिमा के अनुरूप एक भव्य प्रतिमा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार रात दक्षिण मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बरिष्ठ मंत्रियों, नौकरशाहों और नौसेना अधिकारियों के साथ एक बैठक

की अध्यक्षता की। बैठक के बाद ही समिति गठित करने का फैसला लिया गया। इस बीच भारतीय नौसेना ने गुरुवार को बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि उसने इस सप्ताह महाराष्ट्र के मालवण में व्ही शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की परियोजना की संकल्पना की थी। उसने राज्य सरकार के साथ समन्वय में इसे कार्यान्वित किया था। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराया था। वह प्रतिमा की मरम्मत करने और जल्द से जल्द उसे फिर से स्थापित करने के लिए सभी कदमों में सहायता करने को प्रतिबद्ध है। **ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज** मामले में 35 फुट ऊंची मूर्ति के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर लोक निर्माण



विभाग की एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि मूर्ति का निर्माण घटिया गुणवत्ता का था। इसमें इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट खंग आए हुए पाए गए।

26 अगस्त की दोपहर की घटना इस मूर्ति का अनावरण 4 दिसंबर को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके महज आठ महीने बाद ही 26 अगस्त की दोपहर को यह गिर गई थी। इस घटना को लेकर विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) ने महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की है। वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के

इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले दिन में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस घटना के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगी और दोषियों को दंडित करने की प्रतिबद्धता जताई। **कैबिनेट मंत्री के बयान पर बवाल** इससे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर के छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के गिरने से हो सकता है कि कुछ अच्छा हो वाले अपने बयान का बचाव किया। विपक्ष के निशाने पर आए केसरकर ने कहा कि उनका बयान का गलत मतलब निकाला गया। सिंधुदुर्ग के रहने वाले राज्य के शिक्षा मंत्री केसरकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाए, जो शिवाजी की नौसेना का तत्कालीन मुख्यालय था।